



संज्ञा नं० एल. डब्ल्यू./एम. पी. 550

साइसेन्स नं० एल. पी०-४१

लाइसेन्स टु प्रिंट एंड कन्सेशनल एट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 27 फरवरी, 1991

फाल्गुन 8, 1912 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 447/सत्रह-वि-1-1(क)21-1990

लखनऊ, 27 फरवरी, 1991

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश ईंट (सम्भरण का विनियमन) विधेयक, 1990 पर दिनांक 27 फरवरी, 1991 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1991 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश ईंट (सम्भरण का विनियमन) अधिनियम, 1990

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1991)।

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

लोक हित में, उचित मूल्य पर ईंटों का साम्यिक वितरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से ईंटों के सम्भरण को विनियमित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ईंट (सम्भरण का विनियमन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम, 1990 कहा जायेगा।  
विस्तार और प्रारम्भ
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह 12 मई, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में,—

(क) "ईंट" का तात्पर्य ऐसे किसी ज्यामितीय आकार के पकाये हुए मिट्टी के टुकड़े से है जो किसी मट्ठे में पकाया गया हो,

(ख) "मट्ठा" का तात्पर्य ईंटों को आग में पकाने के लिए प्रयुक्त किसी संरचना से है ; और

(ग) "व्यापारी" का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो ईंट का व्यापार करता हो या विक्री के लिए ईंटों का स्टॉक रखता हो और उसके अन्तर्गत उसका प्रतिनिधि या अभिकर्ता भी है ।

ईंटों के मूल्य, सम्भरण, वितरण या उपयोग को विनियमित करने की शक्ति

3—(1) जहां राज्य सरकार की राय हो कि ईंटों के सम्भरण को बनाये रखने या उसमें वृद्धि करने या उनका साम्यिक वितरण करने और उचित मूल्यों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, अधिसूचित आदेश द्वारा, उनके सम्भरण, वितरण, उपयोग और मूल्य को विनियमित करने के लिए व्यवस्था कर सकती है ।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके अधीन दिये गये किसी आदेश में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था हो सकती है :—

(क) लाइसेंसों, अनुज्ञापत्रों द्वारा या अन्यथा ईंटों के संग्रहण, वितरण, परिवहन, अर्जन, सम्भरण, विनिर्माण या उपयोग को विनियमित करने के लिए ;

(ख) उस मूल्य को नियंत्रित करने के लिए जिस पर ईंटों को खरीदा या बेचा जा सकता है ;

(ग) साधारणतः विक्री के लिए रखी गयी ईंटों को, विक्री से रोके जानने को प्रतिषेध करने के लिए ;

(घ) किसी व्यापारी या मट्ठे के स्वामी से ईंटों के सम्बन्ध में ऐसे लेखे और अभिलेख रखने और उनको निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने और ऐसी सम्बन्धित सूचना देने की अपेक्षा करना जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय ;

(ङ) किसी व्यापारी या मट्ठे के स्वामी से स्टॉक में रखे गये या उसके द्वारा निर्मित या प्राप्त किये गये ईंटों के सम्पूर्ण या किसी विनिर्दिष्ट भाग को राज्य सरकार को या केन्द्र सरकार को या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता को या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम को या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को और ऐसी परिस्थितियों में जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो, बेचने की अपेक्षा करने के लिए ;

(च) किन्हीं आनुषंगिक और अनुपूरक विषयों की व्यवस्था करने के लिये जिसके अन्तर्गत विशेषतः परिसरों और गलीयों में प्रवेश करना और उनकी तलाशी लेना, ईंटों का अभिग्रहण करना, लाइसेंसों, अनुज्ञापत्रों और अन्य दस्तावेजों को देना या जारी करना और उनके लिए फीस लेना भी है ।

अस्तित्व

4—(1) जो कोई धारा 3 के अधीन दिये गये किसी आदेश के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन के लिए दृष्टोक्त करता है, वह ऐसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष तक हो सकती है कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा और यदि आदेश में ऐसी व्यवस्था हो तो ऐसे उल्लंघन का विचारण करने वाला कोई न्यायालय निदेश दे सकता है कि ऐसी कोई सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि आदेश का उल्लंघन किया गया है या उसका ऐसा भाग, जिसे न्यायालय उचित समझे राज्य सरकार को समर्पित हो जायगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिससे धारा 3 के अधीन दिये गये आदेश द्वारा कोई कथन करने या कोई सूचना देने की अपेक्षा की जाय,—

(एक) ऐसा कोई कथन करता है या कोई सूचना देता है जिसकी तात्त्विक विशिष्टियाँ मिथ्या हों और जो उसकी जानकारी में मिथ्या हों या उसके पास यह विश्वास करने के कारण हो कि वह मिथ्या है या जिसकी सत्यता में उसे विश्वास न हो, या

(दो) किसी वही, लेखा, अभिलेख, घोषणा, धिक्करी या अन्य दस्तावेज में जिसे रखने या प्रस्तुत करने की किसी आदेश द्वारा उससे अपेक्षा की गयी हो, कोई ऐसा उपयुक्त कथन करता है ;

तो वह ऐसी अधीन के लिए जो तीन वर्ष तक हो सकती है कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा ।

5—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्डित किया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी सचिव, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सहमति या मानानुमति से किया गया है, या उसकी किसी अपेक्षा के कारण हुआ है, तो कम्पनी का ऐसा सचिव, निदेशक, प्रबन्धक, या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगम भी हैं, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के मालीदार से है ।

6—राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे किसी कार्य के लिए जो इस अधिनियम के या इसके अधीन किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो, या किये जाने के लिए अभिप्रेत हो, कोई बाध, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी ।

सद्भावना से की गयी कार्यवाही का संरक्षण;

उत्तर प्रदेश  
असाधारण  
संख्या 12  
सन् 1990

7—(1) उत्तर प्रदेश ईंट (सम्भरण का विनियमन) अध्यादेश, 1990 एतद्वारा निरसित किया जाता है ।

निरसन और  
अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्धों सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,

रवीन्द्र दयाल माथुर,

संयुक्त सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी ।

No. 447(2)/XVII-V-1—1(KA) 21-1990

Dated Lucknow, February 27, 1991

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Eent (Sambharan Ka Viniyaman) Adhiniyam, 1990 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1991) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 27, 1991.

THE UTTAR PRADESH BRICKS (REGULATION OF SUPPLY)  
ACT, 1990

(U. P. ACT No. 6 OF 1991)

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

to provide in public interest, for regulation of supply with a view to securing the equitable distribution of bricks at fair price.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title  
extent and  
commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Bricks (Regulation of Supply) Act, 1990.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on May 12, 1990.

Definitions

2. In this Act,—

(a) 'brick' means any piece of burnt clay having geometrical shape fired in a kiln;

(b) 'kiln' means a structure used for firing bricks; and

(c) 'dealer' means any person who deals in bricks or holds stocks of bricks for sale and includes his representative or agent.

Powers to regulate price, supply, distribution or consumption of bricks

3. (1) Where the State Government is of opinion that it is necessary so to do for maintaining or increasing supplies of bricks or for securing their equitable distribution and availability at fair prices, it may, by notified order, provide for regulating supply, distribution, consumption and price thereof.

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1), an order made thereunder may provide—

(a) for regulating by licences, permits or otherwise the storage, distribution, transport, acquisition, supply, manufacture and consumption of bricks;

(b) for controlling the price at which bricks may be bought or sold;

(c) for prohibiting the withholding from sale, of bricks, ordinarily kept for sale;

(d) for requiring a dealer or kiln owner to maintain and produce for inspection such accounts and records regarding bricks and to furnish such information relating thereto as may be specified in the order;

(e) for requiring a dealer or kiln owner to sell the whole or a specified part of bricks held in stock or produced or received by him to the State Government or the Central Government or to an officer or agent of such Government or to a Corporation owned or controlled by such Government or to such other person or class of persons and in such circumstances as may be specified in the order ;

(f) for any incidental and supplementary matters including in particular the entering and search of premises and vehicles, seizure of bricks, the grant or issue of licences, permits and other documents and the charging of fees therefor.

4. (1) Whoever contravenes or attempts to contravene, or abets the contravention of the provisions of any order made under section 3 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both, and if the order so provides, any court trying such contravention may direct that any property, in respect of which the court is satisfied that the order has been contravened, or such part of it as the court may deem fit shall be forfeited to the State Government. Penalty

(2) Whoever being required by an order made under section 3 to make any statement or furnish any information—

(i) makes any statement or furnishes any information which is false in any material particular and which he knows or has reason to believe to be false, or does not believe to be true, or

(ii) makes any such statement as aforesaid in any book, account, record, declaration, return or other document which he is required by any such order to maintain or furnish ;

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine, or with both.

5. (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Offences by companies

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of, any secretary, director, manager or other officer of the company, such secretary, director, manager or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

*Explanation*—For the purposes of this section—

(a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals, and

(b) "director" in relation to a firm, means a partner in the firm.

Protection of  
action taken in  
good faith

6. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of this Act or any order made thereunder.

Repeal and  
saving

7. (1) The Uttar Pradesh Bricks (Regulation of Supply) Ordinance, 1990, is hereby repealed.

U.P. Or-  
dinance  
12 of 1990

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times

By order,  
R. D. MATHUR,  
Joint Secretary and Joint  
Legal Remembrancer.